

## आवश्यक एवं गैर-आवश्यक सब्सिडी

यह एडिटरियल 16/06/2022 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित "what commodities distribution of commodities should be distributed for free or at a subsidised level" लेख पर आधारित है। इसमें राज्य द्वारा गैर-आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं को प्रदत्त सब्सिडी के रूप में होने वाले अपव्यय के संबंध में चर्चा की गई है और वचिार कथिा गया है कऱिशज्य अपने वतऱरण तंत्र के संवर्धन के लयि कसि प्रकार सर्वोत्तम अभ्यासों का उपयोग कर सकता है।

### संदर्भ

हाल ही में पंजाब सरकार द्वारा 300 युनटि तक मुफ्त बजिली प्रदान करने के लयि एक सब्सिडी योजना की घोषणा की गई, जसिसे एक बार फरि सब्सिडी को लेकर बहस छडि गई है और इसपर मनन की आवश्यकता उत्पन्न हुई है कऱिे कौन-सी आवश्यक वस्तु और सेवाएँ हैं जनिकी समाज के वंचित वर्ग तक पहुँच सुनिश्चित करने हेतु सरकारी प्रयासों की आवश्यकता है।

### सब्सिडी क्या है?

- यह कसिी पण्य/वस्तु (उदाहरण के लयि गेहूँ और चावल, जनिकी सरकार द्वारा खरीद की जाती है) के बाज़ार मूल्य और उस मूल्य के बीच का अंतर है जसि पर उन्हें सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न के रूप में लाभार्थी को बेचा जा रहा है।
- **सब्सिडी की राजकोषीय लागत:**
  - चूँकऱि भारत एक वकिसशील देश है, इसलयि अधिकाधिक जनसंख्या तक सब्सिडी के शुद्ध कवरेज को बढ़ाने के लयि सीमति बजटीय संसाधन ही उपलब्ध हैं।
  - वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में खाद्य सब्सिडी के लयि 06 लाख करोड़ रुपए आवंटित कयि गए थे। कर रयियतों को देखें तो यह वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-2020 में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.9% और 2.5% रही थी।
  - भारत में लंबे समय से [राजसव और जीडीपी का अनुपात](#) गतहीन बना रहा है। वर्ष 2010-11 से वर्ष 2019-20 की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त राजसव प्राप्तयिों 4 प्रतशित से 20.3 प्रतशित के संकीरण दायरे में रही हैं।
  - जबकऱि उल्लेखनीय है कऱिे कऱि वकिसति और उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं में यह अनुपात बहुत अधिक होता है। वर्ष 2019 में यह अनुपात यूके के लयि 36%, यूएसए के लयि 1%, स्वीडन के लयि 48.6%, नीदरलैंड के लयि 43.6% और ब्राजील के लयि 31.5% रहा था।

### सब्सिडी के प्रसार के लयि वतऱरण तंत्र

- लक्षति तरीके से नमिन आय वाले परिवारों के लयि सहायता, जो मुफ्त या सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न और स्वास्थ्य एवं शकिसा जैसी सेवाओं के रूप में उपलब्ध है, जैसे सार्वजनिक वतऱरण प्रणाली।
  - उदाहरण के लयि, लाभार्थी के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) ताकऱि कोई व्यकति अपनी पसंद के अनुसार खुले बाज़ार में कसिी भी खाद्यान्न का चयन करने के लयि स्वतंत्र हो और दूसरी ओर वह PDS के माध्यम से भी सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न का लाभ उठा सके।
- नविशकों और उत्पादकों की चयनति श्रेणयिों को समर्थन देने के लयि प्रोत्साहन (जैसे कॉर्पोरेट करों में कमी), जो सामान्य रूप से या पछिड़े कषेत्रों जैसे कुछ खंडों में नविश को बढ़ावा देने के लयि पेश की गई है; उदाहरण के लयि, [उत्पादन-लकिड प्रोत्साहन \(PLI\)](#)।
  - PLI-वैकल्पिक तरीकों में प्रत्यक्ष बजटीय समर्थन और कर रयियतों के माध्यम से अप्रत्यक्ष समर्थन शामिल हैं। योजनाओं को उनके दुरुपयोग से बचने और उनकी लागत को कम करने के लयि सावधानीपूर्वक अभिलपति करने की भी आवश्यकता है।

### सब्सिडी के चयन का औचित्य क्या होना चाहयि?

- सीमति बजट, खराब लक्षयीकरण और लीकेज के साथ हमें उन वस्तुओं पर ध्यान केंद्रति करने की आवश्यकता है जनिहें 'आवश्यक' (Essential) और 'उत्कृष्ट' (Merit) वस्तु माना जाता है।
  - मुख्य रूप से खाद्यान्न (वशेष रूप से गेहूँ और चावल) सार्वजनिक वतऱरण प्रणाली के माध्यम से लक्षति समूहों को अत्यधिक रयियती मूल्य

पर प्रदान की जाती है।

- इसके अलावा, इस बात के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं कि इस तरह के वितरण ने गरीबी को कम करने में मदद की है।
- वस्तुओं की एक ऐसी श्रेणी भी है जिसे उत्कृष्ट या मेरिट वस्तुओं के रूप में जाना जाता है, जहाँ महत्त्वपूर्ण सकारात्मक बाह्यताएँ (Positive Externalities) उनके उपभोग से संबद्ध होती हैं; उदाहरण के लिये, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित प्रावधान जिसमें मध्याह्न भोजन और नाश्ता शामिल हैं। इन मामलों में ऐसी वस्तुओं के उपयोग का लाभ निकटस्थ उपभोक्ता से अधिक व्यापक समुदाय तक प्रसारित होता है।
- आवश्यक और मेरिट वस्तुओं के सब्सिडीयुक्त या मुफ्त प्रावधान को सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, लेकिन अपव्ययी या लोकलुभावन सब्सिडी के भी कई उदाहरण देखने को मिले हैं। हाल ही में पंजाब सरकार द्वारा 300 यूनटि मुफ्त बजिली की घोषणा इसी श्रेणी की है जिससे बजिली के अपव्ययी उपभोग में अनुचित वृद्धि हुई है।

## आगे की राह

- **अभनिव समाधान:** प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों के उचित लक्ष्यीकरण की आवश्यकता है।
- **वनिधिमन नकिया:** एक कुशल खरीद और सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है जो खरीद और वितरण का प्रबंधन करे। इससे लीकेज और परहार्य प्रशासनिक लागत पर रोक लग सकती है।
- **वस्तुओं और सेवाओं का चयन:** समय की मांग है कि सब्सिडी को केवल आवश्यक और मेरिट वस्तुओं तक ही सीमित रखा जाए।
- **राजकोषीय अवसर की कमी:** वस्तुओं और सेवाओं पर बहुत ही कुशल एवं चयनित सब्सिडी प्रदान करने की आवश्यकता है क्योंकि समग्र वित्तीय सहायता सीमित है।
- **राजस्व का सृजन:** केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर सरकारों को अपने वित्तीय राजस्व को और सुदृढ़ करने के लिये पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है।
- **सामाजिक प्रभाव:** यद्यपि PDS प्रणाली में लीकेज मौजूद हैं, यह व्यक्तियों पर प्रमुख प्रभाव रखता है और इसके लाभ व्यक्तियों से परे सामाजिक एवं सामुदायिक स्तर तक पहुँचते हैं। प्रत्यक्ष आय समर्थन और PLI के लाभ अभी तक मापन योग्य नहीं हैं।
  - इसलिये PDS योजना को जारी रखने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि जहाँ भी संभव हो इसके लीकेज को रोका जाए और इसके साथ-साथ मापन योग्य परिणामों के साथ प्रत्यक्ष आय समर्थन के साथ प्रयोग जारी रखा जाए।

**अभ्यास प्रश्न:** सरकारी राजकोष पर सब्सिडी का तर्कसंगत बोझ डालने के लिये लाभार्थियों के उचित लक्ष्यीकरण की आवश्यकता है। चर्चा कीजिये।

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/essential-and-non-essential-subsidies>

